



# अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.  
दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : [abvpkendra@gmail.com](mailto:abvpkendra@gmail.com)

दिनांक: 19 फरवरी 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

## ‘लावण्या को न्याय’ आंदोलन के एक माह पर अभावपि का देशभर में श्रद्धांजलि मार्च

मतांतरण के दबाव के कारण आत्महत्या करने वाली तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा लावण्या के बलिदान को एक माह पूर्ण होने पर, देश भर में अभावपि की इकाईयों द्वारा मोमबत्ती मार्च निकालकर न्याय की मांग को बल दिया गया एवं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित की गई।

विदित हो कि पिछले एक माह में लावण्या आत्महत्या मामले को कमजोर करने एवं न्याय की मांग को दबाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात, मामला जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास चला गया है। इस बीच, पुलिस द्वारा लावण्या के परिवार पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने के साथ-साथ उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा है। अभावपि आरम्भ से ही, इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन कर रही थी। तमिलनाडु सरकार द्वारा, सुश्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री श्री मुथु रामलिंगम, राष्ट्रीय मंत्री श्री हरीकृष्णा समेत कुल 32 कार्यकर्ताओं को गत 5 दिनों से तमिलनाडु की जेल में प्रतिशोध की भावना के चलते बंद किया गया है। अभावपि के कार्यकर्ताओं ने देश भर में आज मोमबत्ती मार्च निकालकर श्रद्धांजली देते हुए संकल्प किया कि लावण्या की न्याय की लड़ाई को अब और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे।

अभावपि की राष्ट्रीय मंत्री कु. साक्षी सिंह ने कहा, "न्याय की लड़ाई लड़ रहे छात्रों से तमिलनाडु की डीएमके सरकार जिस प्रकार की प्रतिशोध की भावना से व्यवहार कर रही है वह निंदनीय है। कल अभावपि के 12 कार्यकर्ताओं पर पुनः आधारहीन केस दर्ज करना यह साबित करता है कि तमिलनाडु सरकार, येन केन प्रकारेण लावण्या के न्याय के मार्ग को बाधित करना चाहती है।"

अभावपि के राष्ट्रीय मंत्री राकेश दास ने कहा, "लावण्या की मृत्यु के एक माह पूर्ण होने पर अभावपि के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजली देते हुए ये प्रण किया है कि राज्य सरकार की बर्बरता एवं लावण्या के न्याय के युद्ध को वे सभी पूरे शौर्य से लड़ेंगे तथा एक वांछित अंत तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)